दिल्ली, एन.सी.आर. व सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक

उद्योग विहार

निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र

Regd. No.-UPHIN/2004/15489 www.uvindianews.com प्रधान सम्पादक: सत्येन्द्र सिंह

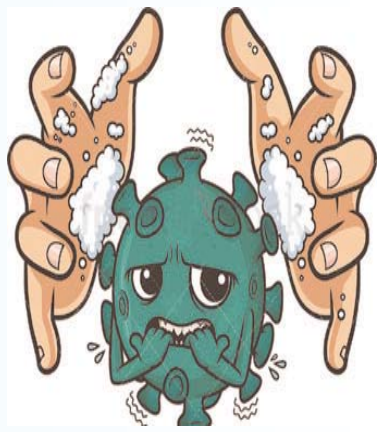

शासन ने कोविड 19 जांच...P-4

वर्ष : 16 ▸ अंक : 12 ▸ गाजियाबाद, दिसंबर, 2020 ▸ मूल्य : 4 रूपया ▸ पृष्ठ : 04 E-mail : udyogviharnp@gmail.com

कोरोना लाइव

9,651,626	9,107,718	140,268	66,991,090
मामले (भारत)	मरीज ठीक हुए	कुल मौतें	मामले (दुनिया)

शीत लहर के बाद भी किसानों में जोश

किसानों की लड़ाई में कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है: लल्लू

गाजियाबाद। ट्रांस हिंडन कृषि कानूनों के विरोध में आठवें दिन भी किसान संगठन यूपी गेट पर बैठे हुए हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के नेताओं का यूपी गेट पर किसानों से मिलने का दौर जारी है इस कड़ी में आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों का आज को आश्वासन दिया कि कांग्रेस किसानों के साथ हर मोर्चे पर कंधे से कंधा मिलाकर यह लड़ाई लड़ेगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर एक और जहां धरने पर बैठे हैं वहीं दूसरी ओर हवन कर सरकार की बुद्धि शुद्धि की कामना भी कर रहे हैं आज देश का अन्नदाता सड़कों पर है लेकिन सरकार किसानों की मांगों की आन देखी कर रही है आखिर सरकार क्यो अपने काले कानून किसानों पर थोपने का कार्य कर रही है। कांग्रेस सदैव किसानों के साथ खड़ी है। कांग्रेस ने सदन में भी इस बिल का विरोध किया था। उसके बाद से किसानों के साथ भी सड़क पर किसानों की लड़ाई लड़ रही है। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि कृषि बिल किसानों की भावना के अनुरूप नहीं है ऐसे में जो सरकार जन भावनाओं का आदर नहीं कर सकती ऐसी सरकार को बने रहने का कोई औचित्य नहीं है।

-उद्योग विहार (दिसंबर 2020)-

गाजियाबाद। पिछले एक सप्ताह से यूपी गेट एवं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेक्स वे पर धरने पर बैठे किसानों का जोश शीत लहर के बावजूद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। खुले आकाश के नीचे धरने पर बैठे किसानों के जत्थे ढोल मंजीरे पर जहां गीत गुनगुनाते हुए नजर आ रहे है, वहीं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेक्स वे पर अलग माहौल देखते हुए बन रहा है। धरने पर बैठे किसानों की मानें तो उनकी वापसी अब तीनों कृषि बिल केंद्र सरकार के द्वारा वापस लिए जाने पर ही होगी।

किसानों ने ये भी संकेत दिए कि यदि आज की वार्ता के दौरान भी किसी तरह का हल निकलता है तो इसके बाद अगले कदम को उठाया जाएगा। यहां बता दे कि भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के किसान शनिवार को यूपी गेट पर पहुंच गए थे। तभी से किसानों के धरना दिया जा रहा है। इस बीच किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सपेक्स वे को भी जाम कर दिया था। बडी संख्या में किसान सडकों पर डेरा जमाए हुए है।

उद्योग विहार

निष्पक्ष पाक्षिक समाचार पत्र

श्रम–जगत

02 P.

E-mail : udyogviharnp@gmail.com

गाजियाबाद, दिसंबर, 2020

MINIMUM WAGES IN DIFFERENT STATES

CATEGORY OF WORKERS	U.P. MINUMUM WAGES GENERAL/ENGINEERING: U.P. GENERAL	U.P. ENGG. BELOW 500	U.P. ENGG. ABOVE 500	DELHI MINIMUM WAGES	RAJASTHAN MINIMUM WAGES	GUJRAT MINIMUM WAGES		PUNJAB MINIMUMWAGES	HARYANA MINIMUMWAGES	UTTARAKHAND MINIMUMWAGES
				MINIMUM WAGES	MINIMUM WAGES	MINIMUM WAGES		MINIMUMWAGES	MINIMUMWAGES	MINIMUMWAGES
	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.		W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.
	01/04/20 TO 30/09/2020	01/02/20 TO 31/07/2020	01/02/20 TO 31/07/2020	10/1/2018	5/1/2019	01/10/2019 TO 31/03/2020		1/3/2019	1/7/2019	01-10-2018 TO 31-03-2019
	BASIC +DA	BASIC +DA	BASIC +DA	BASIC+DA	BASIC+DA	ZONE-I	BASIC+DA ZONE-II	BASIC+DA	BASIC+DA	BASIC+DA
UN SKILLED	8625.00	10086.03	10574.06	14842.00	5850.00	8278.40	8070.40	8776.83	9024.24	8331.00
SEMISKILLED	9487.50	11075.65	11631.46	16341.00	6162.00	8486.40	8278.40	9556.83	*	8924.00
SEMISKILLED-A	*	*	*	*	*	*	*	*	9475.43	*
SEMISKILLED-B	*	*	*	*	*	*	*	*	9949.19	*
SKILLED	10627.50	12295.73	12688.87	17991.00	6474.00	8720.40	8486.40	10453.83	*	9518.00
SKILLED A	*	*	*	*	*	*	*	*	10446.65	*
SKILLED B	*	*	*	*	*	*	*	*	10969	*
HIGHLY SKILLED	*	*	*	*	7774.00	*	*	11485.83	11517.45	*

पेट्रोल का रेट 90 और डीजल 80 के पार, चेक करें अपने शहर का रेट

-उद्योग विहार (दिसंबर 2020)-

नई दिल्ली। सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने लगातार 14वें दिन पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है। आज यानी रविवार को दिल्ली में 28 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। वहीं, डीजल के दाम में 29 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया है। इस बढ़ोतरी के बाद मुंबई और जयपुर में पेट्रोल अब 90 रुपये के पार चला गया है। जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 83 रुपये 41 पैसे हो गई है, जबकि एक लीटर डीजल के लिए 73 रुपये 61 पैसे खर्च करने होंगे। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत दो साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल की कीमतें इस प्रकार हैं..

शहर का नाम	पेट्रोल (रुपये/लीटर)	डीजल (रुपये/लीटर)
दिल्ली	83.41	73.61
मुंबई	90.05	80.23
कोलकाता	84.90	77.81
चेन्नई	86.25	78.97
जयपुर	90.77	82.77

बढ़ती कीमतों की ये है वजह

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट के बाद सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क और बढ़ा दिया था। नवंबर 2014 से जनवरी 2016 तक केंद्र सरकार ने इसमें नौ बार इजाफा किया। इससे कच्चे तेल की कीमतें गिरने का फायदा आम आदमी को नहीं मिला।

17 दिन में पेट्रोल का दाम 2.35 रुपये प्रति लीटर बढ़ा

पेट्रोलियम कंपनियों ने 20 नवंबर से ईंधन कीमतों में फिर संशोधन शुरू किया है। इसके बाद से यह वाहन ईंधन कीमतों में लगातार पांचवीं वृद्धि है। 20 नवंबर से वाहन ईंधन के दाम 14 बार बढ़ाए जा चुके हैं। इससे पहले करीब दो माह तक पेट्रोलियम कंपनियों ने कीमतों में संशोधन नहीं किया था। सितंबर, 2018 के बाद अब वाहन ईंधन के दाम सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। इस तरह से 17 दिन में पेट्रोल के दाम 2.35 रुपये प्रति लीटर बढ़े हैं। इस दौरान डीजल 3.15 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है। कोविड-19 के टीके को लेकर अच्छी खबरों के बीच ब्रेंट कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। 30 अक्टूबर को यह 36.9 डॉलर प्रति बैरल पर थे, जो चार दिसंबर तक करीब 34 प्रतिशत बढ़कर 49.5 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच चुके हैं।

ऐसे दोगुना हो जाता है पेट्रोल-डीजल का रेट

पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। अगर केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारों का वैट हटा दें तो डीजल और पेट्रोल का रेट लगभग 27 रुपये लीटर रहता, लेकिन चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार, दोनों किसी भी कीमत पर टैक्स नहीं हटा सकती। क्योंकि राजस्व का एक बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। इस पैसे से विकास होता है।

हर सुबह होती तय होती हैं कीमतें

दरअसल विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत के आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कीमतों की समीक्षा के बाद रोजाना पेट्रोल और डीजल के रेट तय करती हैं। इंडियन ऑयल , भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की दरों में संशोधन कर जारी करती हैं।

अगले वित्त वर्ष के अंत तक कोविड-पूर्व के स्तर पर पहुंचेगी अर्थव्यवस्थाः नीति आयोग

देश की आर्थिक वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष (2021-22) के अंत तक कोविड-19 के पूर्व के स्तर पर पहुंच जाएगी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने रविवार को यह बात कही। कुमार ने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में गिरावट आठ प्रतिशत से कम रहने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट के अनुमान को 9.5 प्रतिशत से घटकर 7.5 प्रतिशत कर दिया है।

विनिर्माण गतिविधियां बढ़ने से ऋद्ध में सुधार

नीति आयोग के उपाध्यक्ष कुमार ने अगले वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर के अनुमान के बारे में पूछे जाने पर पीटीआई-भाषा से कहा, "हम निश्चित रूप से 2021-22 के अंत तक कोविड-19 के पूर्व के स्तर पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी में गिरावट आठ प्रतिशत से कम रहने का अनुमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने विनिर्माण गतिविधियां बढ़ने से चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में उम्मीद से बेहतर सुधार दर्ज किया है। जुलाई-सितंबर तिमाही में अर्थव्यवस्था में गिरावट घटकर 7.5 प्रतिशत रह गई है। बेहतर उपभोक्ता मांग से आगे अर्थव्यवस्था की स्थिति और सुधरने की उम्मीद है। देश के कृषि क्षेत्र पर कुमार ने कहा कि नीति आयोग रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दे रहा है। इसमें कृषि उत्पादन की लागत में भारी कटौती करने करने की क्षमता है। साथ ही इसका पर्यावरण पर भी काफी सकारात्मक असर पड़ेगा।

विनिवेश से 2.10 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य

संपत्ति के मौद्रिकरण पर कुमार ने कहा, "यह काम मौजूदा समय में जारी है और इसपर उच्चस्तर से ध्यान दिया जा रहा है। हम इस काम को जारी रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि संपत्ति के मौद्रिकरण लक्ष्य को हासिल किया जा सके। सरकार का चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 2.10 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है। इसमें से 1.20 लाख करोड़ रुपये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) में हिस्सेदारी बिक्री से और 90,000 करोड़ रुपये वित्तीय संस्थानों में सरकार की हिस्सेदारी बिक्री से जुटाए जाएंगे।

बैंकिंग क्षेत्र में और सुधारों की जरूरत

बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों के बारे में पूछे जाने पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि इस क्षेत्र का और विस्तार किए जाने की जरूरत है और साथ ही प्रतिस्पर्धा भी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि देश का निजी ऋण से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अनुपात काफी कम है। वहीं अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मामले में यह 100 प्रतिशत से अधिक है। कुमार ने कहा कि ऐसे में हमें निजी कर्ज बढ़ाने की जरूरत है, यह तभी हो सकेगा जबकि हमारे बैंकिंग क्षेत्र का विस्तार होगा।

LEGAL INFOSOLUTIONS PVT LTD.

❖ LABOUR LAWS ❖ HR MANAGEMENT

❖ PAYROLL OUTSOURCING MANAGEMENT

❖ SOCIAL AUDIT & COMPLIANCE'S)

http://www.legalipl.com

BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.- 201002

The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C, Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India

9818036460

legalipl243@gmail.com

उद्योग विहार
निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र
Editorial
03
P.
E-mail : udyogviharnp@gmail.com
गाजियाबाद, दिसंबर, 2020

सम्पादकीय

उम्मीद का टीका

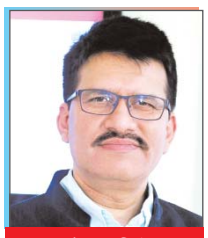

सत्येन्द्र सिंह

अब कोरोना विषाणु का चक्र तोड़ने को लेकर उम्मीद बलवती हो गई है। ब्रिटेन दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है, जिसने अपने यहां कोरोना के टीके को अंतिम मंजूरी दी है। वहां की दवा एवं स्वास्थ्य उत्पाद नियामक एजेंसी ने दवा कंपनी फाइजर द्वारा तैयार टीके को पंचानबे फीसद तक सुरक्षित और प्रभावकारी करार दिया है। अब वहां यह टीका आम लोगों के उपयोग के लिए बाजार में उपलब्ध हो सकेगा। पिछले दिनों सीरो और आक्सफर्ड के टीके को लेकर जिस तरह विवाद खड़ा हो गया था, उससे लग रहा था कि कोरोना टीकों के परीक्षण में बड़ा अवरोध उत्पन्न हो गया है। सीरो के टीके का एक प्रतिनिधि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। उसका उसके दिमाग पर बुरा असर दिखाई देने लगा था, जिसके चलते उसने कंपनी पर भारी भरपाई का दावा ठोक दिया था। उसके बचाव में भारतीय स्वास्थ्य विभाग को भी उतरना पड़ा। फाइजर के टीके को मंजूरी मिलने से निस्संदेह दूसरे टीकों के परीक्षण को कुछ बल मिलेगा। वह टीका दूसरे देशों के बाजारों में भी उतारा जा सकेगा। यों कोविड 19 जैसे विषाणु को रोकने वाले टीकों का परीक्षण काफी जटिल होता है। इसका हर चरण जोखिम भरा होता है। जिन लोगों पर ऐसे टीकों का परीक्षण किया जाता है, उनके जान को भी खतरा रहता है। कई बार परीक्षण में इस्तेमाल टीके के प्रतिकूल असर के चलते प्रतिनिधि में आजीवन स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बनी रह सकती हैं। इसलिए बहुत सारे विशेषज्ञ दवाओं के मनुष्य पर परीक्षण का विरोध करते रहे हैं। मगर दिक्कत यह है कि बिना मनुष्य पर परीक्षण के दवा के बारे में अंतिम रूप से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। इसी क्रम में सीरो के टीके का बुरा प्रभाव नजर आया था। भारत के स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि यहां भी जल्दी ही कोरोना का टीका बाजार में आ जाएगा। सीरो के टीके में पाई गई खामियों को जल्दी दूर कर लिया जाएगा। हमारे यहां कोविड 19 का टीका जल्दी से जल्दी बाजार में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस विषाणु के चक्र को तोड़ने के लिए आजमाए जा चुके अब तक के सारे उपाय विफल साबित हुए हैं। जब से बंदी खुली है, लोग मनमाने तरीके से बाहर निकलने लगे हैं। उन्हें नाक–मुंह ढंकने जैसे एहतियाती उपायों पर अमल न करने के लिए भी दंडित करना पड़ रहा है। कई राज्यों में दुबारा आंशिक बंदी लगानी पड़ी है। दूरदराज के गांवों और कस्बों में इस लापरवाही से अधिक खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग की चिंता है कि किस तरह इसके संक्रमण का चक्र तोड़ा जाए। फिलहाल शुरूआती चरण में सबको टीका उपलब्ध कराना सरकारों के सामने बड़ी चुनौती होगी, मगर जितने भी लोगों तक इसकी पहुंच संभव हो पाएगी, उतने से ही इस पर काफी हद तक लगामा लगाई जा सकेगी। हालांकि टीके के बाजार में आने के बाद भी हाथ धोने, उचित दूरी बनाए रखने, नाक–मुंह ढंक कर ही बाहर निकलने और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ लेते रहने की जरूरत बनी रहेगी। किसी भी विषाणु को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। कोरोना का विषाणु भी खत्म नहीं होने वाला। टीका सिर्फ लोगों में उससे लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर सकेगा। इसलिए लोगों से यह अपेक्षा सदा बनी रहेगी कि वे इस विषाणु से बचाव के एहतियाती उपाय इस्तेमाल करते रहें। ब्रिटेन में टीके के आ जाने से निस्संदेह स्वास्थ्य विज्ञानियों का मनोबल बढ़ा है कि वे इस चुनौतीपूर्ण संक्रमण को रोकने की दिशा में कामयाबी के बहुत करीब पहुंच गए हैं।

गांवों की उपेक्षा कर अनियोजित तरीके से बसाए जा रहे शहर पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा

कोरोना की उत्तरकालीन व्यवस्थाओं पर चिन्तन करते हुए बढ़ते पर्यावरण एवं प्रकृति विनाश को नियंत्रित करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, इसके लिये बढ़ते शहरीकरण को रोकना एवं गांव आधारित जीवनशैली पर बल देना होगा। भले ही शहरीकरण को आर्थिक और सामाजिक वृद्धि का सूचक माना जाता है। लेकिन अनियंत्रित शहरीकरण बड़ी समस्या बन रहा है। भारत में तो शहरीकरण ने अनेक समस्याएं खड़ी कर दी हैं, आम जनजीवन न केवल स्वास्थ्य बल्कि जीवनमूल्यों की दृष्टि से जटिल होता जा रहा है। आर्थिक विकास भी इसी कारण असंतुलित हो रहा है। ऐसे में जब कोरोना जैसे अभूतपूर्व संकट के दौरान बेतरतीब जीवनशैली से भरे शहर अचानक डराने लगें तब हमारे गांवों ने ही शहरी लोगों को पनाह दी। इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसी योजनाएं बनाई जाएं जिससे गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों को होने वाले पलायन की रफ्तार कुछ थम सके। पर्यावरण एवं प्रकृति को हो रहे नुकसान का मूल कारण अनियोजित शहरीकरण है। बीते दो दशकों के दौरान यह प्रवृत्ति पूरे देश में बढ़ी है। लोगों ने दिल्ली एवं ऐसे ही महानगरों की सीमा से सटे खेतों पर अवैध कालोनियां काट लीं। इसके बाद जहां कहीं सड़क बनी, उसके आसपास के खेत, जंगल, तालाब को वैध या अवैध तरीके से कंक्रीट के जंगल में बदल दिया गया। देश के अधिकांश उभरते शहर अब सड़कों के दोनों ओर बेतरतीब बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल स्वतन्त्र भारत के विकास के लिए हमने जिन नक्शे कदम पर चलना शुरू किया उसके तहत बड़े–बड़े शहर पूंजी केन्द्रित होते चले गये और रोजगार के स्रोत भी ये शहर ही बने। शहरों में सतत एवं तीव्र विकास और धन का केन्द्रीकरण होने की वजह से इनका बेतरतीब विकास स्वाभाविक रूप से इस प्रकार हुआ कि यह राजनीतिक दलों के अस्तित्व और प्रभाव से जुड़ता चला गया, लेकिन पर्यावरण एवं प्रकृति से कटता गया। इसी कारण गांव आधारित अर्थ–व्यवस्थाएं लडखड़ाने लगी हैं। बढ़ते शहरीकरण के बावजूद एक बड़ा सच यह भी है कि आज भी देश में सत्तर फीसद आबादी गांवों में बसती है। यानी अगर शहरीकरण को विकास का पैमाना मान भी लिया जाए तो हम दुनिया के ज्यादातर देशों से अभी बहुत पीछे हैं। बहरहाल, कितने भी पीछे हों, लेकिन जितना और जैसा समस्याबहुल शहरीकरण हो रहा है उसने गंभीर सोच–विचार के लिए हमें मजबूर कर दिया है। खासकर तब, जब शहरीकरण की मौजूदा चाहत के चलते अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक देश की शहरी आबादी गांवों की आबादी से ज्यादा हो जाएगी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में कहा कि उम्मीद के मुताबिक भारत की 40 प्रतिशत आबादी 2030 तक शहरी क्षेत्रों में रहेगी और हमें इसके लिए छह से आठ सौ मिलियन वर्ग मीटर का अर्बन स्पेस बनाना होगा। पुरी के अनुसार 100 स्मार्ट सिटी में 1,66,000 करोड़ रुपये की लगभग 4,700 परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जो प्रस्तावित कुल परियोजनाओं का लगभग 81 प्रतिशत है। सरकार के

पर्यावरण एवं प्रकृति को हो रहे नुकसान का मूल कारण अनियोजित शहरीकरण है। बीते दो दशकों के दौरान यह प्रवृत्ति पूरे देश में बढ़ी है। लोगों ने दिल्ली एवं ऐसे ही महानगरों की सीमा से सटे खेतों पर अवैध कालोनियां काट लीं।

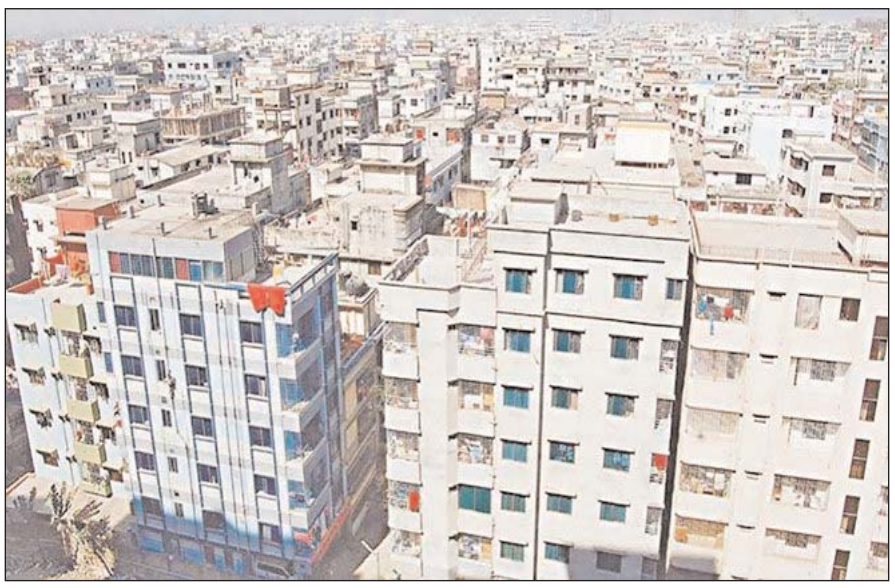

सामने एक बड़ी चुनौती है बढ़ते शहरीकरण को नियोजित करने की। शहरों में अधिक आबादी रहने का मतलब है कि उनका आधारभूत ढांचा संवारने का काम युद्ध स्तर पर किया जाए ताकि वे बढ़ी हुई आबादी का बोझ सहने में समर्थ रहें और साथ ही रहने लायक भी बने रहें। लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। हमारे जिन भी नीति नियंताओं और विभागों पर भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर शहरी ढांचे का निर्माण करने की जिम्मेदारी होती है, वे शहरों के नियोजन के नाम पर कामचलाऊ ढंग से काम करते हैं। नया शहरीकरण अनियोजित और मनमाना होता है, जहां पर सिर्फ कंक्रीट के जंगल होते हैं तो पुराने इलाके में पूरा ढांचा ही जर्जर और गंदगी से भरा होता है। इसका नतीजा यह होता है कि हमारे देश में शहरों की परिभाषा तरह–तरह के प्रदूषणों, गंदगी, वायु दूषित होने, अतिक्रमण, अपराध, ट्रैफिक जाम, जलभराव, झुग्गी बस्तियों, अनियंत्रित निर्माण और कूड़े के पहाड़ के बगैर पूरी ही नहीं होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले ही कार्यकाल में स्मार्ट सिटी की अवधारणा लेकर आए थे। लेकिन यह योजना भी भ्रष्टाचार, पैसे की तंगी और अनियमितता की भेंट चढ़ गई। यह योजना केंद्र सरकार और राज्यों के बीच टकराव का कारण भी बन गई। इसके साथ ही एक समस्या यह भी है कि सिर्फ फ्लाईओवर, मेट्रो आदि का निर्माण करके हमारे नीति नियंता शहरीकरण के नाम पर अपनी पीठ थपथपा लेते हैं लेकिन क्या इससे शहरों में रहने लायक स्थिति बन जाती है ? क्या बढ़ता शहरीकरण पर्यावरण एवं प्रकृति के लिये गंभीर खतरा नहीं बन रहा है? भारत की अर्थ–व्यवस्था आज भी गांव, कृषि, पशुपालन आधारित है। असली भारत आज भी गांवों में ही बसता है जिसमें देश की करीब 70 फीसद आबादी रहती है। दरअसल वास्तविकता यह है कि हमने आजादी के बाद से लेकर अब तक गांवों एवं गांव आधारित स्वस्थ, उन्नत एवं आत्मनिर्भर जीवन को नकारा है। गांवों की उन्नति एवं उन्हें बेहतर बनाने की बजाए हमने उनकी उपेक्षा की है, जिससे वहां से पलायन बढ़ा है। हमारी सरकारें शहरीकरण के नाम पर हजारों करोड़ रुपया खर्च करने के लिए तैयार हैं लेकिन गांवों में मूलभूत सुविधाओं के नाम पर भी पैसा देने से उन्हें तकलीफ होने लगती है। गांवों को लेकर सरकार की नीतियां विसंगतिपूर्ण रही हैं। खेती को घाटे का सौदा बता दिया गया और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को निराश करने वाली व्यवस्था में बदल दिया गया। खेती को मुनाफे का सौदा बनाने और गांवों की अर्थव्यवस्था में निवेश करने की बजाय पूरा ध्यान गांवों की जनसंख्या को शहरों में खींच लेने पर रहा।

गांवों के प्रति उपेक्षा से जुड़ी हकीकत यह है कि बड़ी आबादी वहां रहने के बावजूद पेयजल की सप्लाई नहीं है, चिकित्सा–सुविधाएं नगण्य हैं। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत देखी जाए तो गांव काफी पीछे हैं लेकिन इसके बावजूद बिजली कटौती की सबसे ज्यादा मार ग्रामीण इलाकों पर ही पड़ती है। गांवों में शिक्षा का ढांचा आज भी जर्जर है। बीते सात दशकों में रोजगार सृजन को लेकर गांवों की अनदेखी की गई है। गांवों की परिवहन समस्याओं के प्रति भी हमारी सरकारें उदासीन रही हैं। हमारे देश में संस्कृति, मानवता और जीवन का विकास नदियों के किनारे एवं गांवों में ही हुआ है। सदियों से नदियों की अविरल धारा और उसके तट पर मानव जीवन फलता–फूलता रहा है। बीते कुछ दशकों में विकास की ऐसी धारा बही कि नदी की धारा आबादी के बीच आ गई और आबादी की धारा को जहां जगह मिली वह बस गई। और यही कारण कि हर साल कस्बे नगर बन रहे हैं और नगर महानगर। बेहतर रोजगार, आधुनिक जनसुविधाएं और उज्ज्वल भविष्य की लालसा में अपने पुश्तैनी घर–बार छोड़कर शहर की चकाचौंध की ओर पलायन करने की बढ़ती प्रवृत्ति का परिणाम है कि देश में एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या लगभग 350 हो गई है जबकि 1971 में ऐसे शहर मात्र 151 थे। यही हाल दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों का है।

महानगर केवल पर्यावरण प्रदूषण ही नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रदूषण की भी गंभीर समस्या उपजा रहे हैं। लोग अपनों से, मानवीय संवेदनाओं से, अपनी लोक परंपराओं व मान्यताओं से कट रहे हैं। जिसके कारण परम्परा एवं संस्कृति में व्याप्त पर्यावरण एवं प्रकृति संरक्षण के जीवन सूत्रों से हम दूर होते जा रहे हैं, ऐसे कारणों का लगातार बढ़ना, नगरों– महानगरों का बढ़ना, जनसंख्या बहुल क्षेत्रों का सुरसा सतत विस्तार पाना और उसकी चपेट में प्रकृति और उसकी नैसर्गिकता का आना गंभीर स्थितियां हैं। इंसान की क्षमता, जरूरत और योग्यता के अनुरूप उसे अपने मूल स्थान पर यानी गांवों में अपने सामाजिक सरोकारों के साथ जीवन–यापन का हक मिले, विकास का अवसर मिले। यदि विकास के प्रतिमान ऐसे होंगे तो शहर की ओर लोगों का पलायन रूकेगा। इससे हमारी धरती को कुछ राहत अवश्य मिलेगी। प्रकृति एवं पर्यावरण पर मंडरा रहे खतरों में भी तभी कमी आयेगी।

TAKSHAK
MANAGEMENT INDIA PVT LTD
EVENTS MANAGEMENT
PR MANAGEMENT
ARTISTS MANAGEMENT
http://www.takshakindia.com
BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.-201002
The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C,
Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India
9818036460
takshakindia@gmail.com

उद्योग विहार

निष्पक्ष नागरिक सरोकार पत्र

04 P.

E-mail : udyogviharnp@gmail.com

गाजियाबाद, दिसंबर, 2020

चिकित्सा शिक्षा में बदलाव का विरोध

-उद्योग विहार (दिसंबर 2020)-

गाजियाबाद। देश की शिक्षा नीति में बदलाव के साथ चिकित्सा शिक्षा में भी बड़ा बदलवा हुआ है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के अनुसार इस बदलाव में सभी पद्वति के छात्रों को एमबीबीएस की डिग्री देने का प्रावधान है और आयुर्वेदिक चिकित्सकों को दो साल की पढ़ाई के बाद सर्जरी की अनुमति देने का भी प्रावधान है। आईएमए इस बदलाव का विरोध कर रहा है। इस विरोध के चलते आईएमए 11 दिसंबर को देश व्यापी हड़ताल करने जा रही है। इसमें गाजियाबाद के निजी डॉक्टर्स भी शामिल होंगे। चिकित्सा शिक्षा में किए गए बदलाव के विरोध में आंदोलन की रूपरेखा के बारे में जानकारी देने के लिए बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईएमए गाजियाबाद के अध्यक्ष डॉ. आशीष अग्रवाल ने कहा कि इससे आयुर्वेदिक चिकित्सक और एलोपैथिक डॉक्टर्स में अंतर करना मुश्किल हो जाएगा।

इसके साथ ही यदि केवल दो साल के कोर्स के बाद आयुर्वेदिक चिकित्सकों को सर्जरी की अनुमति दी जाएगी तो इसके परिणाम बेहद बुरे हो सकते हैं। उन्होंने कहा यह एक तरह का खिचड़ी तंत्र विकसित हो जाएगी जो ना केवल देश वासियों के लिए बुरा होगा बल्कि विदेशों में भी देश के डॉक्टर्स की छवि धूमिल करेगा। उन्होंने कहा कि आज विदेशों में 60 प्रतिशत डॉक्टर्स भारतीय हैं और उनकी प्रतिष्ठा वहां के मूल डॉक्टर्स से कहीं ज्यादा है। डॉ. वीबी जिंदल ने कहा कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए सरकार को आयुर्वेद कॉलेज खोलने चाहिए और आयुर्वेदिक दवाओं पर शोध करवाने चाहिए। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद प्राचीन भारतीय पद्धति और समाज में आयुर्वेदिक दवाओं की स्वीकार्यता बहुत ज्यादा है, इसलिए इस विधा का सम्मान करना चाहिए। इस विधा को किसी और विधा में मिलाया नहीं जाना चाहिए। डॉ. नवनीत वर्मा ने कहा कि देश में सर्जनों के मुकाबले दवाओं की ज्यादा जरूरत है। इसलिए आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए उस क्षेत्र में सुविधाएं, शोध को बढ़ाने के साथ गुणवत्ता में भी सुधार करना चाहिए। डॉ. वाणी पुरी ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत जो पढ़ाया जाएगा वह खिचड़ी ज्ञान होगा उससे अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे, इसमें पूरा संदेह है। सरकार चिकित्सा की अलग-अलग पैथी को आपस में मिलाने की जगह सभी को अलग-अलग सुविधाएं प्रदान करे और सभी का समुचित विकास करे।

11 दिसंबर को हड़ताल पर रहेंगे निजी डॉक्टर्स

आईएमए अध्यक्ष ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा में किए गए इस बदलाव के विरोध में 8 दिसंबर को आईएमए भवन पर दोपहर में 3 से 4 बजे तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा और 11 दिसंबर को निजी डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान केवल इमरजेंसी और कोविड सेवाएं जारी रखी जाएंगी।

अनंत उन्नति फाउंडेशन ने बांटे गर्म कपड़े

-उद्योग विहार (दिसंबर 2020)-

गाजियाबाद। अनंत उन्नति फाउंडेशन के द्वारा वहां पढ़ने वाले बच्चों एवं झुग्गियों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े वितरित किए गए। फाउंडेशन का निरंतर यही प्रयास रहता है कि जरूरतमंद लोगों को कपड़े, भोजन एवं जरूरत की चीजें उपलब्ध कराई जा सके। गत वर्ष भी लगभग 1000 लोगों को गर्म कपड़े फाउंडेशन के द्वारा वितरित किए गए। कोरोना जैसी महामारी में भी फाउंडेशन ने हजारों परिवारों को राशन उपलब्ध कराया। फाउंडेशन में पढ़ने वाले बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है जिसमें बच्चों को किताबें, पेंसिल, शिक्षण सामग्री एवं भोजन उपलब्ध कराया जाता है साथ ही उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी समाधान किया जाता है।

फाउंडेशन की प्रमुख प्रीति चौधरी ने बताया कि यह कार्य आगे भी निरंतर इसी प्रकार फाउंडेशन के द्वारा किए जाते रहेंगे। इस कार्य में फाउंडेशन के निदेशक विकास पाल और उन्नति चौधरी एवं वॉलिंटियर्स मोनाजा साजिद, सोनवी अग्रवाल एवं वर्षा उपस्थित रहे।

शासन ने कोविड 19 जांच बढ़ाने के दिए निर्देश

-उद्योग विहार (नवंबर 2020)-

गाजियाबाद। वेडिंग सीजन और सर्दियों को देखते हुए शासन ने जिले में कोरोना जांच बढने के निर्देश दिए हैं। अब जिले में रोजाना 1700 आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अब तक यह लक्ष्य केवल 1100 था। वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि रोजाना 1200 सैंपल ग्रेटर नोएडा स्थित जिम्स में जांच के लिए भेजे जाएंगे, जबकि 500 आरटी-पीसीआर जांच एमएमजी अस्पताल स्थित लैब में की जाएंगी। इसके साथ ही जिले में प्रतिदिन 2550 एंटीजन जांच की जाएंगी। उन्होंने बताया कि शासनादेश के मुताबिक कुल जांचों की 40 फीसदी आरटी-पीसीआर और 60 फीसदी एंटीजन जांच की जानी हैं। वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) की मदद से मैपिंग कराई जा रही है।

मैपिंग के मुताबिक दिल्ली से सटे क्षेत्रों में ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इन क्षेत्रों में साहिबाबाद, इंदिरापुरम, करहेड़ा-2 और विजयनगर शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग इन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा सैंपलिंग कर रहा है। सैंपलिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग जनपद में 14 स्थाई बूथों का संचालन कर रहा है। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग पर भी जोर दिया जा रहा है। हर पॉजिटिव के 30 कॉन्टेक्ट तलाशे जा रहे हैं और उनकी कोविड जांच कराई जा रही है। इसके अलावा जनपद में संचालित 13 निजी कोविड अस्पतालों में से 10 में स्वास्थ्य विभाग की ओर से एंटीजन किट उपलब्ध कराई जा रही हैं। हर निजी कोविड अस्पताल में रोजाना औसतन 50 एंटीजन जांचें की जाती हैं।

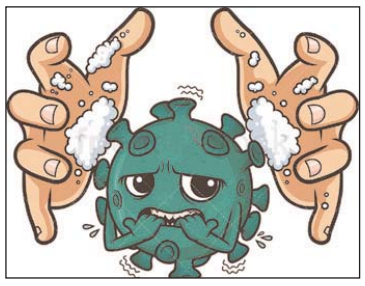

अब जिले में रोजाना होंगे 1700 आरटी-पीसीआर टेस्ट

जांच को गति देने के लिए 2550 एंटीजन जांच होंगी

उन्होंने बताया कि डब्लूएचओ के सहयोग से की जा रही मैपिंग से संवेदनशील क्षेत्रों में की जानकारी अपडेट रहती है। मैपिंग के अनुसार संवेदनशील क्षेत्रों में कोविड जांच बढ़ाई जा रही है ताकि कोरोना वायरस की श्रंखला को तोड़ने में मदद मिल सके। सीएमओ ने जनपद वासियों से अपील की है कि जुकाम, सूखी खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने पर कोविड जांच कराएं।

रेडीसन के पीछे कबाड़ियों की बढ़ती संख्या से जीडीए चिंतित

-उद्योग विहार (नवंबर 2020)-

गाजियाबाद। रेडीसन होटल के ठीक पीछे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जीडीए की बेशकीमती जमीन पर कब्जा जमा कर बैठे कबाडियों के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद से कबाडियों की बढती संख्या ने जीडीए अधिकारियों को मुश्किल में डाल दिया है। जीडीए अधिकारी ये तय नहीं कर पा रहे है कि बढती संख्या पर किस तरह से कंट्रोल करें। यहां बता दे कि एक लंबे समय से बडी संख्या में कबाडी रेडीसन होटल के पीछे कब्जा किए हुए है। कुछ कबाडियों के द्वारा मेडिकल वेस्ट को भी ठिकाने लगाया जा रहा है। हाल में जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के चेयरमेन भूरे लाल ने मौके का जायजा लिया तो उजागर हुआ कि जमीन का स्वामी जीडीए है। हैरत का पहलू ये है कि जीडीए ने जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की पहल की तो कबाडी उच्च न्यायालय चले गए। उच्च न्यायालय ने मूल भूत सुविधा के साथ इन कबाडियों को बसाने के आदेश दिए थे। इस निर्णय के बाद से जीडीए के आला अधिकारी दुविधा में है।

भूरे लाल के निरीक्षण के बाद हरकत में आया था प्राधिकरण

वहीं कौशांबी आरडब्लूए कारवां के अध्यक्ष विनय कुमार मित्तल ने कहा कि मौजूदा में उत्पन्न हालात के लिए जीडीए पूरी तरह से जिम्मेदार है। जीडीए में डिवीजन और प्रवर्तन की लंबी चैडी फौज है तो उसे चाहिए कि वह निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

एमएलसीः स्नातक सीट पर भाजपा के दिनेश कुमार गोयल ने जीत तय कर रचा इतिहास

-उद्योग विहार (दिसंबर 2020)-

गाजियाबाद। मेरठ खंड स्नातक सीट पर एमएलसी चुनाव में भी भाजपा ने बाजी मार ली है। शनिवार सुबह तक चली प्रथम वरीयता के मतों की गिनती में भाजपा प्रत्याशी दिनेश गोयल ने निवर्तमान एमएलसी और निर्दलीय प्रत्याशी हेम सिंह पुंडीर को 27 हजार 80 मतों से पराजित कर दिया। हेम सिंह पुंडीर को 15 हजार 972 वोट मिले हैं। कुल मिलाकर दोपहर 12 बजे 11वें राउंड में दिनेश गोयल 27 हजार 128 मतो से आगे चल रहे है। गोयल की जीत तय मानते हुयें समर्थको ने दोपहर बाद ही अतिशबाजी व ढोल धमाको के बीच जश्न मनाना शुरू कर दिया। दोपहर 12बजे बाद अब द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती चल रही है, जिसे औपचारिकता माना जा रहा है। इससे पहले भाजपा मेरठ शिक्षक सीट जीत चुकी है। मेरठ खंड स्नातक सीट की प्रथम वरीयता के मतों की गिनती में भाजपा प्रत्याशी 27080 मतों से जीत चुके हैं। भाजपा प्रत्याशी दिनेश गोयल को कुल 43 हजार 52 वोट मिले। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी निवर्तमान एमएलसी हेम सिंह पुंडीर को 15972वोट मिले हैं। दोपहर 12 बजे बाद 11वें राउंड की स्थिति में कांग्रेस के उम्मीदवार को 7514बोट तथा सपा प्रत्याशी शमसाद अली को 7081मिल पाये तो वहीं बुलंदशहर के शिकारपुर चेयरमैन की पत्नि अर्चना शर्मा निर्दलीय उम्मीदवार ने 6191 बोट पाये तसे मोदीनगर के इटवा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एंव व्यापारी नेता प्रिंस कंसल मात्र 780 मतो तक सिमटे दिखे। इस स्नातक सीट पर ही शिक्षक सुनील कुमार त्यागी ने 4551 बोट हासिल किये तो वही निर्दलीय उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह इस राउंड में 3909 मत ले चुके। स्नातक सीट के राउंडवाईज परिणामो में भाजपा की चल रही बढत को देख दिनेश कुमार गोयल की जीत तय मानते हुयें अब समर्थको व पार्टी कार्यकर्ताओं ने मतगणना स्थल से थोडी दूरी पर ही जश्न मनाना शुरू कर दिया।

गोयल की जीत पर समर्थको व पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना किया शुरू

एक दूसरे को मिठाई बाँटकर गले लगाकर खुशी के इस इजहार में अतिशबाजी ढोल धमाको के बीच कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस तरह पहली बार मेरठ-सहारनपुर खंड सीट पर शिक्षक और स्नातक दोनों में भाजपा की पहली बार हुई जीत ने इतिहास रच डाला। चुनाव आयोग के नियमों के तहत द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती चल रही है जो देर शाम तक जारी रहेगी। प्रथम वरीयता के मतों की गिनती का काम पूर्ण होते ही भाजपाइयों में खुशी की लहर देखी जा रही है।

मै. लीगल इन्फोशोल्यूशन्स प्रा0लि0, मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक **"सत्येन्द्र सिंह"** द्वारा मै. बी.एफ.एल. इन्फोटैक लि. प्रेस, सी-9, सैक्टर-3, नोएडा से छपवाकर बी.ई.-243, (ग्राउण्ड फ्लोर) अवन्तिका, गाजियाबाद से प्रकाशित किया।

फोन : 0120-4122901/4108794 **मोबाइल नं. :** 9818036460/9818697406 **E-mail :** udyogviharnp@yahoo.com **संस्थापक :** शीतला प्रसाद सिंह **प्रधान सम्पादक :** सत्येन्द्र सिंह **सम्पादक :** बबिता सिंह **सह सम्पादक :** राजेश सिंह